किया गया व्यय नीचे दिये गये अनुसार था:—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	व्यय की स्वीकृत अधिकतम सीमायें	राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यय
1985–86	89.65	105.40
1986–87	141.45	157.58
1987–88	433.16	561.84

उपर्युक्त अधिकतम सीमाओं के अलावा, राज्य सरकार को सूखा राहत के लिये 1986–87 में 63 करोड़ रुपये के तथा 1987–88 में 43 करोड़ रुपये के खाद्यान्न आवंटित किये गये थे।

इसके अलावा, अल्पावधि सहकारी ऋणों को मध्यम अवधि के ऋणों में परिवर्तित करने तथा चारे की ढुलाई पर आर्थिक सहायता के रूप में दिये गये राज्य सरकार के योगदान को वास्तव में किये गये व्यय की सीमय तक स्वीकृति भी प्रदान की गई थी।

औद्योगिक घरानों पर विज्ञापन कर लगाया जाना

2356. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे औद्योगिक घरानों के नाम क्या हैं जो अपने उत्पादों का काफी बड़े पैमाने पर विज्ञापन कर रहे हैं ; और

(ख) क्या सरकार विज्ञापनों पर खर्च की जा रही भारी राशि पर विज्ञापन कर लगाने का विचार रखती है ; यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मंत्री (श्री वी० के० गढ़वी): (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अन्तर्गत कम्पनियों द्वारा विज्ञापन पर किये गये व्यय को लाभ तथा हानि के लेखे में अलग से दिखाये जाने की तब तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि यह कम्पनी के कुल राजस्वों के एक प्रतिशत अथवा 5000/– रु०, इनमें से जो भी अधिक हो, उससे अधिक न हो जाये। इस के अतिरिक्त कुछ कम्पनियां इस व्यय को या तो विज्ञापन व्यय, विपणन व्यय अथवा बिक्री संवर्धन व्यय रूप में दर्ज करती है। इसको ध्यान में रखते हुये उन औद्योगिक घरानों का पता लगाना संभव नहीं है जो अपने उत्पादों को बड़े पैमाने पर विज्ञापित कर रहे हैं।

(ख) सरकार द्वारा विज्ञापनों पर कर लगाये जाने पर विचार किया गया है परन्तु अनेक कारणों से, जिसमें समाचार-पत्रों की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव की शामिल है, ऐसा करना व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

सूखा राहत के संबंध में अमरीका से बातचीत

2357. **श्री सन्तोष बागडोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखा राहत के संबंध में संयुक्त राज्य अमरीका के अधिकारियों से हाल ही में कोई बातचीत हुई है और इस संबंध में कोई रूप रेखा तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।